

EXAM GENIUS

Presents

GENIUS CURRENT AFFAIRS

In Bilingual

05 MAY 2026



Achieve Success with Exam Genius - Your Ultimate Guide to Reasoning Mastery !



Ques: What is the key change in FDI norms announced by the Government of India in May 2026?

प्रश्न: मई 2026 में भारत सरकार द्वारा FDI नियमों में क्या प्रमुख बदलाव किया गया है?

- A) Ban on Chinese investments / चीनी निवेश पर प्रतिबंध
- B) Allowing 10% Chinese stake firms via automatic route / 10% चीनी हिस्सेदारी वाली कंपनियों को ऑटोमैटिक रूट से अनुमति
- C) Increase in FDI limit to 100% / FDI सीमा को 100% करना
- D) Removal of FEMA regulations / FEMA नियमों को हटाना
- E) Mandatory approval for all foreign investments / सभी विदेशी निवेश के लिए अनिवार्य मंजूरी

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India has eased FDI norms under Foreign Exchange Management Act for companies with up to 10% Chinese shareholding.
- भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत 10% तक चीनी हिस्सेदारी वाली कंपनियों के लिए नियमों में ढील दी है।
- Such companies can now invest in India through the automatic route, subject to sectoral conditions.
- ऐसी कंपनियां अब क्षेत्रीय शर्तों के तहत ऑटोमैटिक रूट से निवेश कर सकती हैं।
- The decision came into effect from May 1, 2026, as notified by the Ministry of Finance.
- यह निर्णय 1 मई 2026 से वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित होकर लागू हुआ।
- The relaxation is based on amendments to Press Note 3 of 2020 approved by the Union Cabinet of India.
- यह ढील 2020 के प्रेस नोट 3 में संशोधन पर आधारित है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी।
- It aims to boost foreign investment in sectors like electronics and manufacturing.
- इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण क्षेत्रों में विदेशी निवेश बढ़ाना है।
- However, the relaxation does not apply to entities registered in China, Hong Kong, or countries sharing land borders with India.
- हालांकि यह ढील चीन, हांगकांग या भारत से भूमि सीमा साझा करने वाले देशों की संस्थाओं पर लागू नहीं होगी।





- Higher or controlling Chinese stakes will still require government approval.
- अधिक या नियंत्रित हिस्सेदारी के लिए अभी भी सरकारी मंजूरी आवश्यक होगी।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- FEMA Full Form – Foreign Exchange Management Act
- FEMA का पूर्ण रूप – विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
- Introduced – 1999
- लागू – 1999
- Nodal Ministry – Ministry of Finance
- संबंधित मंत्रालय – वित्त मंत्रालय
- DPIIT Full Form – Department for Promotion of Industry and Internal Trade
- DPIIT का पूर्ण रूप – उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
- Press Note 3 Year – 2020
- प्रेस नोट 3 वर्ष – 2020

EXAM
Genius





Ques: Under RBI's revised loan restructuring guidelines for disaster-hit areas, what is the mandatory provisioning requirement for banks and NBFCs?

प्रश्न: आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए RBI के संशोधित लोन पुनर्गठन दिशानिर्देशों के तहत बैंकों और NBFCs के लिए अनिवार्य प्रावधान (Provisioning) कितना है?

- A) 2%
- B) 3%
- C) 5%
- D) 7%
- E) 10%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Reserve Bank of India has introduced revised guidelines for loan restructuring in disaster-hit areas, providing greater flexibility to banks and NBFCs.
- भारतीय रिजर्व बैंक ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोन पुनर्गठन के संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे बैंकों और NBFCs को अधिक लचीलापन मिलेगा।
- The new framework will come into effect from 1 July 2026.
- यह नया ढांचा 1 जुलाई 2026 से लागू होगा।
- It allows lenders to proactively restructure loans without waiting for borrower requests.
- इसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता के अनुरोध का इंतजार किए बिना ही ऋण पुनर्गठन कर सकते हैं।
- A key feature is the mandatory 5% provisioning requirement, where lenders must set aside 5% of the outstanding loan value.
- इसका प्रमुख प्रावधान 5% अनिवार्य प्रावधान है, जिसमें ऋणदाताओं को बकाया ऋण का 5% अलग रखना होगा।
- Borrowers have a 135-day opt-out window from the date of disaster declaration.
- उधारकर्ताओं को आपदा घोषणा की तिथि से 135 दिनों का ऑप्ट-आउट विकल्प मिलेगा।
- RBI rejected requests to reduce provisioning to 2%, citing the need for better risk coverage in uncertain recovery scenarios.
- RBI ने प्रावधान को 2% करने के अनुरोध को अस्वीकार किया, यह कहते हुए कि अनिश्चित परिस्थितियों में





जोखिम कवर जरूरी है।

Eligibility conditions include:

- Only standard accounts are eligible
- Loans should not be overdue by more than 30 days at the time of disaster
- Also the requests to extend eligibility up to 89 days overdue were rejected to ensure that the relief targets genuine disaster-affected borrowers.

पात्रता शर्तें:

- केवल स्टैंडर्ड खाते पात्र होंगे
- आपदा के समय ऋण 30 दिनों से अधिक ओवरड्यू नहीं होना चाहिए
- साथ ही, बकाया ऋण के लिए पात्रता को 89 दिनों तक बढ़ाने के अनुरोधों को भी अस्वीकार कर दिया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राहत का लाभ आपदा से वास्तविक रूप से प्रभावित उधारकर्ताओं को ही मिले।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Effective Date – 1 July 2026
- प्रभावी तिथि – 1 जुलाई 2026
- Provisioning Requirement – 5%
- प्रावधान आवश्यकता – 5%
- Opt-out Window – 135 days
- ऑप्ट-आउट अवधि – 135 दिन
- Eligibility – Standard Accounts (≤ 30 days overdue)
- पात्रता – स्टैंडर्ड खाते (30 दिन से कम ओवरड्यू)





Ques: The Asian Development Bank (ADB) announced a \$70 billion plan for which sectors in the Asia-Pacific region?

प्रश्न: एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 70 बिलियन डॉलर की योजना किन क्षेत्रों के लिए घोषित की?

- A) Agriculture & Health / कृषि एवं स्वास्थ्य
- B) Education & Tourism / शिक्षा एवं पर्यटन
- C) Energy & Digital Infrastructure / ऊर्जा एवं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
- D) Defence & Space / रक्षा एवं अंतरिक्ष
- E) Banking & Finance / बैंकिंग एवं वित्त

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Asian Development Bank announced a \$70 billion programme for energy and digital infrastructure.
- एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऊर्जा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 70 बिलियन डॉलर की योजना की घोषणा की।
- The announcement was made during the 59th Annual Meeting held in Samarkand, Uzbekistan.
- यह घोषणा समरकंद, उज़्बेकिस्तान में की गई।
- The plan aims to expand energy connectivity and digital networks across the Asia-Pacific region by 2035.
- इस योजना का उद्देश्य 2035 तक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ऊर्जा और डिजिटल नेटवर्क का विस्तार करना है।
- It includes \$50 billion for Pan-Asia Power Grid Initiative and \$20 billion for digital connectivity.
- इसमें 50 बिलियन डॉलर पावर ग्रिड और 20 बिलियन डॉलर डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए हैं।
- It will strengthen cross-border electricity trade and broadband access.
- यह सीमा-पार बिजली व्यापार और ब्रॉडबैंड पहुंच को मजबूत करेगा।
- ADB President Masato Kanda emphasized long-term economic growth.
- एडीबी अध्यक्ष Masato Kanda ने दीर्घकालिक विकास पर जोर दिया।





Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Asian Development Bank Established – 1966
- एडीबी की स्थापना – 1966
- Headquarters – Manila, Philippines
- मुख्यालय – मनीला, फिलीपींस
- President – Masato Kanda (2026)
- अध्यक्ष – Masato Kanda (2026)
- Members – 69 Countries
- सदस्य – 69 देश
- Objective – Promote economic development and regional cooperation
- उद्देश्य – आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना

EXAM
Genius





RECENT LOANS AND AGREEMENTS :

- Indian Railway Finance Corporation (IRFC) has agreed to extend a ₹13,615 crore loan to the Telangana Government.
- Indian Railway Finance Corporation (IRFC) ने Telangana सरकार को ₹13,615 करोड़ का ऋण देने पर सहमति दी है।
- Export-Import Bank of India has extended a \$100 million (approx ₹830 crore) loan to Africa Finance Corporation (AFC).
- एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने अफ्रीका फाइनेंस कॉर्पोरेशन (AFC) को \$100 मिलियन (लगभग ₹830 करोड़) का ऋण प्रदान किया है।
- World Bank and Asian Development Bank have jointly committed USD 1,600 million for Amaravati Capital Phase-I.
- विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने मिलकर अमरावती कैपिटल फेज-I के लिए USD 1,600 मिलियन देने का वादा किया है।
- World Bank has approved a \$225 million loan for Rajasthan.
- World Bank ने राजस्थान के लिए 225 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है।
- Japan International Cooperation Agency signed Official Development Assistance (ODA) loan agreements worth ¥275 billion (approx ₹16,420 crore) with the Government of India.
- जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने भारत सरकार के साथ ¥275 बिलियन (लगभग ₹16,420 करोड़) के ODA ऋण समझौते किए।
- Bank of Baroda received a USD 500 million loan from an IFSC Banking Unit located in GIFT City.
- बैंक ऑफ बड़ौदा को GIFT सिटी, गुजरात स्थित IFSC बैंकिंग यूनिट से 500 मिलियन USD का ऋण प्राप्त हुआ।
- DCM Shriram Limited secured USD 90 million funding from the International Finance Corporation (IFC).
- DCM श्रीराम लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) से USD 90 मिलियन की फंडिंग प्राप्त की।





Ques: Who has been appointed as the Festival Director for the 57th International Film Festival of India (IFFI)?

प्रश्न: 57वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के लिए फेस्टिवल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Karan Johar / करण जौहर
- B) Sanjay Leela Bhansali / संजय लीला भंसाली
- C) Rajkumar Hirani / राजकुमार हिरानी
- D) Ashutosh Gowariker / आशुतोष गोवारिकर
- E) Anurag Kashyap / अनुराग कश्यप

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Ministry of Information and Broadcasting has appointed Ashutosh Gowariker as the Festival Director for the 57th edition of IFFI.
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आशुतोष गोवारिकर को IFFI के 57वें संस्करण के लिए फेस्टिवल डायरेक्टर नियुक्त किया है।
- The festival will be held in Goa.
- यह महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा।
- International Film Festival of India is South Asia's oldest film festival, established in 1952.
- IFFI दक्षिण एशिया का सबसे पुराना फिल्म महोत्सव है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी।
- The festival is jointly organised by National Film Development Corporation and the Entertainment Society of Goa.
- इस महोत्सव का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।





Recent Appointment in different departments :

- Praseon Joshi : Chairman of Prasar Bharati
- प्रसून जोशी : प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया
- Mr. Rajesh Kumar Agarwal : Director at Power Finance Corporation (PFC) (Replaced Sandeep Kumar)
- श्री राजेश कुमार अग्रवाल: पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) में निदेशक (संदीप कुमार के स्थान पर)
- Herjit S Bhalla : India Business CEO of Dabur
- हरजीत एस भल्ला: डाबर के भारत व्यापार प्रमुख
- Parminder Singh : CEO of Reliance Enterprise Intelligence Limited (REIL), a joint venture(JV) between Reliance Intelligence Limited and Meta
- परमिंदर सिंह: रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड (आरईआईएल) के सीईओ, जो रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड और मेटा के बीच एक संयुक्त उद्यम (जेवी) है।
- Srikanth Velamakanni : Chairperson of NASSCOM (succeeds Sindhu Gangadharan)
- श्रीकांत वेलामकन्नी: नैसकॉम के अध्यक्ष (सिंधु गंगाधरन के स्थान पर)
- Ashok Kumar Lahiri : Vice Chairman of NITI Aayog (replaces Suman K. Bery)
- अशोक कुमार लाहिड़ी: नीति आयोग के उपाध्यक्ष (सुमन के. बेरी के स्थान पर)
- Kishor Patil, Co-founder, MD & CEO of KPIT Technologies : Vice Chairperson National Association of Software and Service Companies(Nasscom)
- किशोर पाटिल, सह-संस्थापक, प्रबंध निदेशक और सीईओ, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज: राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनियों के संघ (नैसकॉम) के उपाध्यक्ष
- John Ternus : CEO of Apple
- जॉन टर्नस: एप्पल के सीईओ





Ques: Cabinet may approve ₹37,500 crore scheme related to which sector?

प्रश्न: ₹37,500 करोड़ की प्रस्तावित योजना किस क्षेत्र से संबंधित है?

- A) Solar Energy / सौर ऊर्जा
- B) Coal Gasification / कोयला गैसीफिकेशन
- C) Wind Energy / पवन ऊर्जा
- D) Nuclear Energy / परमाणु ऊर्जा
- E) Hydropower / जलविद्युत

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Union Cabinet of India is likely to approve a ₹37,500 crore incentive scheme for coal gasification projects.
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ₹37,500 करोड़ की कोयला गैसीफिकेशन योजना को मंजूरी दे सकता है।
- The aim is to boost clean energy production and reduce import dependence.
- इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना और आयात निर्भरता कम करना है।
- The scheme targets reduction in imports of LNG, urea, methanol, and other fuels.
- यह योजना LNG, यूरिया, मेथनॉल आदि के आयात को कम करने पर केंद्रित है।
- Maximum financial assistance will be up to ₹3,000 crore per project.
- प्रत्येक परियोजना के लिए अधिकतम सहायता ₹3,000 करोड़ तक होगी।
- The initiative supports India's target of achieving 100 million tonnes coal gasification capacity by 2030.
- यह पहल 2030 तक 100 मिलियन टन लक्ष्य का समर्थन करती है।
- The scheme promotes better utilisation of domestic coal resources.
- यह घरेलू कोयला संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देती है।
- Coal gasification converts coal into syngas, which is used to produce fuels and chemicals.
- कोयला गैसीफिकेशन में कोयले को सिंथेटिक गैस में बदला जाता है।

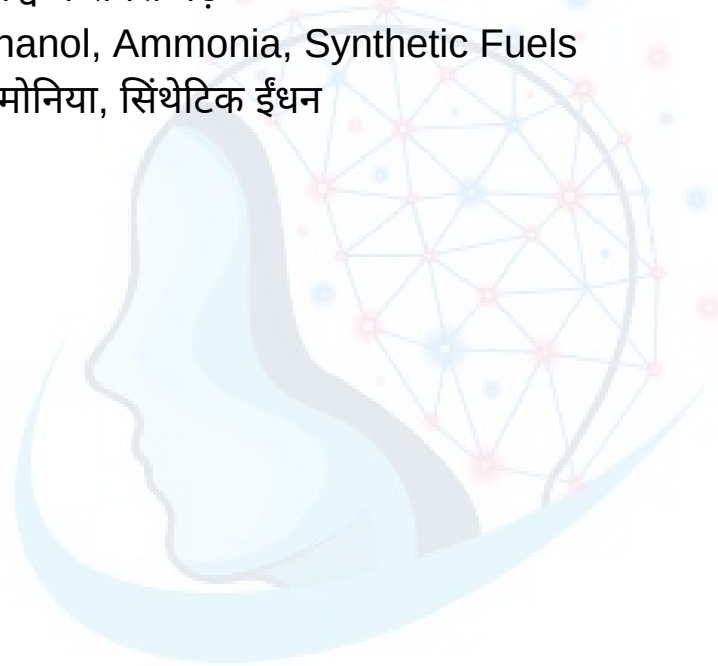
Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Coal Gasification – Conversion of coal into gas (syngas)





- कोयला गैसीफिकेशन – कोयले को गैस में बदलने की प्रक्रिया
- Target – 100 Million Tonnes by 2030
- लक्ष्य – 2030 तक 100 मिलियन टन
- Ministry – Ministry of Coal
- मंत्रालय – कोयला मंत्रालय
- India Coal Reserves – Among the largest in the world
- भारत के कोयला भंडार – विश्व में सबसे बड़े
- Major Products – Methanol, Ammonia, Synthetic Fuels
- प्रमुख उत्पाद – मेथनॉल, अमोनिया, सिंथेटिक ईंधन



EXAM
Genius





Ques: PRASHAST 2.0, developed by NCERT, is primarily used for what purpose?

प्रश्न: NCERT द्वारा विकसित PRASHAST 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) Online examination system / ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली
- B) Teacher training platform / शिक्षक प्रशिक्षण मंच
- C) Digital attendance system / डिजिटल उपस्थिति प्रणाली
- D) Scholarship distribution / छात्रवृत्ति वितरण
- E) Early identification of children with disabilities / दिव्यांग बच्चों की प्रारंभिक पहचान

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- PRASHAST 2.0 (Pre-Assessment Holistic Screening Tool) is a digital platform developed by National Council of Educational Research and Training.
- PRASHAST 2.0 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे NCERT द्वारा विकसित किया गया है।
- It is designed to help schools identify children with disabilities at an early stage and promote inclusive education.
- इसका उद्देश्य स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की प्रारंभिक पहचान करना और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है।
- It is a mobile app-based screening tool used in schools.
- यह एक मोबाइल ऐप आधारित स्क्रीनिंग टूल है, जिसका उपयोग स्कूलों में किया जाता है।
- The platform can identify 21 types of disabilities as defined under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.
- यह प्लेटफॉर्म RPWD अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की पहचान कर सकता है।





Recent News Headlines Related to launched Apps/portals :

- The Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) is launching the E-PRAAPTI portal for members with old or inactive EPF accounts.
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पुराने या निष्क्रिय EPF खातों वाले सदस्यों के लिए E-PRAAPTI पोर्टल लॉन्च कर रहा है।
- The Central Bureau of Investigation (CBI) launched an AI-powered chatbot named "Abhay".
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने "अभय" नामक AI-आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है।
- Life Insurance Corporation of India launched two mobile apps — MyLIC and Super Sales Saathi.
- भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने दो मोबाइल ऐप — MyLIC और Super Sales Saathi लॉन्च किए।
- Dr. Jitendra Singh announced that the Anusandhan National Research Foundation (ANRF) is developing the SARAL AI platform.
- डॉ. जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) SARAL AI प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है।
- The Telangana government has launched the Bhu Bharati portal, an integrated land record management system aimed at simplifying land registration and record services. The new system replaces the earlier Dharani portal.
- तेलंगाना सरकार ने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है, जो भूमि पंजीकरण और अभिलेख सेवाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से बनाया गया एक एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली है। यह नई प्रणाली पूर्ववर्ती धरानी पोर्टल का स्थान लेगी।
- The JanSamarth Portal was launched by Prime Minister Narendra Modi on June 6, 2022. The portal integrates 15 credit-linked Central Government schemes. As of March 20, 2026, around 254 lenders have been onboarded on the platform. Since its launch, about 41.14 lakh applications worth ₹1,06,306 crore have been processed.





Ques: Who has been appointed as the new Chairman & Managing Director (CMD) of HAL?

प्रश्न: HAL के नए चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) DK Sunil / डीके सुनील
- B) Ravi K / रवि के
- C) Rakesh Sharma / राकेश शर्मा
- D) Ajay Kumar / अजय कुमार
- E) Arvind Saxena / अरविंद सक्सेना

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Ravi K has assumed charge as the 22nd Chairman & Managing Director of Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
- रवि के ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के 22वें CMD का पदभार संभाला।
- He succeeded DK Sunil, who retired on April 30.
- उन्होंने डीके सुनील का स्थान लिया, जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए।
- Ravi K has over 30 years of experience in aerospace and defence sectors.
- रवि के के पास एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में 30+ वर्षों का अनुभव है।
- Earlier, he served as Director (Operations) at HAL.
- इससे पहले वह HAL में डायरेक्टर (ऑपरेशंस) थे।
- He played a key role in achieving HAL's 'Maharatna' status.
- उन्होंने HAL को 'महारत्न' दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- He contributed to projects like HAL Tejas and HAL Prachand.
- उन्होंने LCA तेजस और LCH प्रचंड जैसे प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया।
- His vision is to make HAL a globally competitive aerospace company.
- उनका लक्ष्य HAL को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनी बनाना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Hindustan Aeronautics Limited Headquarters – Bengaluru
- मुख्यालय – बेंगलुरु





- Founded – 1940
- स्थापना – 1940
- Status – Maharatna PSU
- स्थिति – महारत्न पीएसयू



EXAM
Genius





Ques: Who has been appointed as the brand ambassador for the F1 Sim Racing India Open 2026?

प्रश्न: F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026 के लिए ब्रांड एंबेसडर किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Virat Kohli / विराट कोहली
- B) Rohit Sharma / रोहित शर्मा
- C) Hardik Pandya / हार्दिक पांड्या
- D) KL Rahul / केएल राहुल
- E) Shreyas Iyer / श्रेयस अय्यर

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Shreyas Iyer has been appointed as the official brand ambassador for the F1 Sim Racing India Open 2026.
- श्रेयस अय्यर को F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026 का आधिकारिक ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है।
- The initiative is backed by Formula 1.
- यह पहल फॉर्मूला 1 द्वारा समर्थित है।
- It is being organised by Mumbai Falcons Racing Limited.
- इसका आयोजन मुंबई फाल्कन्स रेसिंग लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।
- The company has received rights to host an official Formula 1-sanctioned sim racing competition in India.
- कंपनी को भारत में आधिकारिक फॉर्मूला 1 द्वारा मान्यता प्राप्त सिम रेसिंग प्रतियोगिता आयोजित करने के अधिकार मिले हैं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Event – F1 Sim Racing India Open 2026
- आयोजन – F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026
- Organizer – Mumbai Falcons Racing Limited
- आयोजक – मुंबई फाल्कन्स रेसिंग लिमिटेड
- Backed By – Formula 1
- समर्थन – फॉर्मूला 1
- Brand Ambassador – Shreyas Iyer
- ब्रांड एंबेसडर – श्रेयस अय्यर





Recent Headlines Related to Brand Ambassador :

- **Milind Soman** : Brand ambassador of BHIVE Workspace
- **मिलिंद सोमन**: BHIVE वर्कस्पेस के ब्रांड एंबेसडर

- **Shivam Dube** : Brand ambassador of Mobilla, one of India's leading mobile accessories and power solutions brands
- **शिवम दुबे**: मोबिला के ब्रांड एंबेसडर, जो भारत के अग्रणी मोबाइल एक्सेसरीज और पावर सॉल्यूशंस ब्रांडों में से एक है

- **Carlos Alcaraz** : Global Brand Ambassador of Infosys
- **कार्लोस अल्काराज़**: इंफोसिस के ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर

- **Bollywood actor Ahaan Panday** : First-ever Indian brand ambassador for Davidoff Parfums
- **बॉलीवुड अभिनेता अहान पांडे**: डेविडॉफ परफ्यूम्स के पहले भारतीय ब्रांड एंबेसडर

- **Ranveer Singh** : Brand Ambassador of Jindal stainless
- **रणवीर सिंह**: जिंदल स्टेनलेस स्टील के ब्रांड एंबेसडर

- **Double Olympic medallist Blanka Vlašić** : International Event Ambassador for the World 10K Bengaluru 2026.
- **डबल ओलंपिक पदक विजेता ब्लांका व्लासिच** : वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026 का इंटरनेशनल इवेंट एंबेसडर

- **Sudarsan Pattnaik, an internationally acclaimed sand artist** : Brand Ambassador for Census 2027 by the Government of India
- **अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक**, भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किए गए हैं।

- **A. R. Rahman** : Yamaha Music India Private Limited
- **ए. आर. रहमान**: यामाहा म्यूजिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड





Ques: Which state has become India's first paperless judiciary state?

प्रश्न: भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य कौन बना है?

- A) Assam / असम
- B) Sikkim / सिक्किम
- C) Kerala / केरल
- D) Gujarat / गुजरात
- E) Himachal Pradesh / हिमाचल प्रदेश

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Sikkim has been declared India's first paperless judiciary state.
- सिक्किम को भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया है।
- The announcement was made by Justice Surya Kant.
- यह घोषणा न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा की गई।
- The declaration took place during a conclave held in Gangtok.
- यह घोषणा गंगटोक में आयोजित सम्मेलन के दौरान की गई।
- Prem Singh Tamang termed it a historic step toward a digital justice system.
- प्रेम सिंह तमांग ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया।
- The initiative promotes e-filing and digital case management systems.
- यह पहल ई-फाइलिंग और डिजिटल केस मैनेजमेंट को बढ़ावा देती है।
- It aims to make justice delivery faster, transparent, and accessible.
- इसका उद्देश्य न्याय प्रणाली को तेज, पारदर्शी और सुलभ बनाना है।
- The move supports India's vision of Viksit Bharat 2047.
- यह कदम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को समर्थन देता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Capital – Gangtok
- राजधानी – गंगटोक
- Chief Minister – Prem Singh Tamang
- मुख्यमंत्री – प्रेम सिंह तमांग
- High Court – Sikkim High Court
- उच्च न्यायालय – सिक्किम उच्च न्यायालय





Recent News Headlines Related to First in india and world :

- India is setting up its first green methanol plant in Kutch, Gujarat.
- भारत गुजरात के कच्छ में अपना पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट स्थापित कर रहा है।
- Rocklink India Private Limited inaugurated India's first integrated lithium-ion battery and rare earth recycling facility.
- Rocklink India Private Limited ने भारत का पहला एकीकृत लिथियम-आयन बैटरी और रेयर अर्थ रीसाइक्लिंग प्लांट शुरू किया।
- Bihar's first-ever structured pulse procurement initiative has been launched under this mission.
- इस मिशन के तहत बिहार की पहली संरचित दाल खरीद पहल शुरू की गई है।
- India's first intra-city drone delivery trials were conducted in Bengaluru.
- भारत का पहला इंटर-सिटी ड्रोन डिलीवरी ट्रायल Bengaluru में किया गया
- Skyroot Aerospace's Vikram-1 is set to become India's first privately developed orbital-class rocket.
- Skyroot Aerospace का Vikram-1 भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट बनने जा रहा है।
- The Indian Institute of Technology (IIT) Ropar has launched India's first fully integrated Agricultural Intelligence Ecosystem.
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रोपड़ ने भारत का पहला पूर्ण रूप से एकीकृत कृषि इंटेलिजेंस इकोसिस्टम लॉन्च किया है।
- Eveready Industries India Ltd. has commissioned India's first dedicated alkaline battery manufacturing facility.
- Eveready Industries India Ltd. ने भारत की पहली समर्पित अल्कलाइन बैटरी निर्माण इकाई शुरू की है।
- Prime Minister Narendra Modi will visit Rajasthan to dedicate India's first greenfield integrated refinery-cum-petrochemical complex at Pachpadra to the nation.





Ques: The Samarth Panchayat Portal is primarily used for what purpose?

प्रश्न: समर्थ पंचायत पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) Agricultural Subsidy Distribution / कृषि सब्सिडी वितरण
- B) Digital Revenue Collection by Panchayats / पंचायतों द्वारा डिजिटल राजस्व संग्रह
- C) Rural Employment Generation / ग्रामीण रोजगार सृजन
- D) Health Monitoring System / स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली
- E) Education Management / शिक्षा प्रबंधन

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Samarth Panchayat portal is being expanded across multiple states in India.
- समर्थ पंचायत पोर्टल का कई राज्यों में विस्तार किया जा रहा है।
- It is designed for digital, UPI-based collection of Own Source of Revenue (OSR) by Gram Panchayats.
- यह ग्राम पंचायतों द्वारा UPI आधारित डिजिटल माध्यम से स्वयं के राजस्व (OSR) के संग्रह के लिए बनाया गया है।
- The Ministry of Panchayati Raj is rolling it out in Assam, Uttar Pradesh, and Maharashtra.
- पंचायती राज मंत्रालय इसे असम, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लागू कर रहा है।
- The portal has already been successfully piloted in Himachal Pradesh and Chhattisgarh.
- इसका सफल पायलट हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया गया है।
- It helps panchayats generate and collect tax and non-tax revenues digitally.
- यह पंचायतों को कर और गैर-कर राजस्व डिजिटल रूप से एकत्र करने में मदद करता है।
- The platform enables online payments, record maintenance, and revenue tracking.
- यह ऑनलाइन भुगतान, रिकॉर्ड प्रबंधन और ट्रैकिंग की सुविधा देता है।
- The initiative aims to enhance financial autonomy and transparency at the grassroots level.
- इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर वित्तीय स्वायत्तता और पारदर्शिता बढ़ाना है।
- It also supports better policy planning and efficient local governance.
- यह बेहतर नीति निर्माण और कुशल स्थानीय शासन को बढ़ावा देता है।





Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Ministry – Ministry of Panchayati Raj
- मंत्रालय – पंचायती राज मंत्रालय
- OSR – Own Source of Revenue
- OSR – स्वयं का राजस्व स्रोत
- UPI – Unified Payments Interface
- UPI – एकीकृत भुगतान इंटरफेस
- Objective – Digital Governance & Financial Empowerment
- उद्देश्य – डिजिटल गवर्नेंस और वित्तीय सशक्तिकरण

EXAM
Genius





Ques: Under which initiative did India deploy the Aarogya Maitri portable healthcare system in Jamaica?

प्रश्न: भारत ने जमैका में आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थकेयर सिस्टम किस पहल के तहत तैनात किया?

- A) Ayushman Bharat Initiative / आयुष्मान भारत पहल
- B) BHISHM Initiative / भीष्म पहल
- C) Digital India Mission / डिजिटल इंडिया मिशन
- D) Make in India / मेक इन इंडिया
- E) National Health Mission / राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- India deployed the Aarogya Maitri portable healthcare system in Jamaica under its Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) framework.
- भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) ढांचे के तहत जमैका में आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थकेयर सिस्टम तैनात किया।
- This was done under the BHISHM Initiative.
- यह भीष्म पहल के तहत किया गया।
- BHISHM stands for Bharat Health Initiative for Sahyog Hita & Maitri.
- BHISHM का पूर्ण रूप भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित और मैत्री है।
- It is an emergency medical aid initiative providing portable hospital systems during disasters.
- यह एक आपातकालीन चिकित्सा सहायता पहल है, जो आपदा के समय पोर्टेबल अस्पताल सुविधा प्रदान करती है।
- The BHISHM Cube (mobile hospital unit) contains medicines, ICU setup, and surgical equipment.
- भीष्म क्यूब (मोबाइल अस्पताल यूनिट) में दवाइयाँ, ICU सेटअप और सर्जिकल उपकरण होते हैं।
- It can treat around 200 patients.
- यह लगभग 200 मरीजों का उपचार कर सकता है।





Ques: Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) acquired a 51% stake in which company?

प्रश्न: मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) ने 51% हिस्सेदारी किस कंपनी में खरीदी है?

- A) Cochin Shipyard / कोचीन शिपयार्ड
- B) Colombo Dockyard PLC / कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी
- C) Hindustan Shipyard / हिंदुस्तान शिपयार्ड
- D) Garden Reach Shipbuilders / गार्डन रीच शिपबिल्डर्स
- E) Larsen & Toubro Shipbuilding / लार्सन एंड टुब्रो शिपबिल्डिंग

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) has acquired a 51% controlling stake in Colombo Dockyard PLC (CDPLC).
- मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी में 51% हिस्सेदारी खरीदी है।
- This marks India's first international shipyard acquisition.
- यह भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय शिपयार्ड अधिग्रहण है।
- The deal is valued at around ₹250 crore (\$53 million).
- इस सौदे का मूल्य लगभग ₹250 करोड़ (\$53 मिलियन) है।
- The acquisition strengthens India's presence in the Indian Ocean Region.
- यह अधिग्रहण हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को मजबूत करता है।
- It is strategically and commercially significant for both India and Sri Lanka.
- यह भारत और श्रीलंका दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
- The deal expands CDPLC's access to global markets and Indian clients.
- यह सौदा CDPLC की वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाता है।
- MDL plans to expand into ship repair and high-margin maritime services.
- MDL शिप रिपेयर और समुद्री सेवाओं में विस्तार करेगा।
- The acquisition also includes a \$40 million investment infusion.
- इसमें \$40 मिलियन का अतिरिक्त निवेश भी शामिल है।
- It will boost employment, skill development, and R&D capabilities.
- इससे रोजगार, कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।





Ques: Who has been appointed as the President of the National Company Law Tribunal (NCLT)?

प्रश्न: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Uday Kotak / उदय कोटक
- B) T. S. Tirumurti / टी. एस. तिरुमूर्ति
- C) Rajnish Kumar / रजनीश कुमार
- D) Sanjiv Khanna / संजीव खन्ना
- E) Anupinder Singh Grewal / अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The Union Government has appointed Anupinder Singh Grewal as the President of the National Company Law Tribunal.
- केंद्र सरकार ने अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
- He will serve a term of 5 years or until the age of 67, whichever is earlier.
- वह 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक (जो पहले हो) पद पर रहेंगे।
- NCLT is a quasi-judicial body that adjudicates issues related to companies in India.
- NCLT एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो भारत में कंपनियों से संबंधित मामलों का निपटारा करता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- NCLT Formed – 1 June 2016
- NCLT गठन – 1 जून 2016
- Headquarters (Principal Bench) – New Delhi
- मुख्यालय (प्रधान पीठ) – नई दिल्ली
- Nature – Quasi-Judicial Body
- प्रकृति – अर्ध-न्यायिक निकाय





Ques: The 'Missing Link' project is associated with which expressway?

प्रश्न: 'मिसिंग लिंक' परियोजना किस एक्सप्रेसवे से संबंधित है?

- A) Yamuna Expressway / यमुना एक्सप्रेसवे
- B) Delhi–Mumbai Expressway / दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे
- C) Mumbai–Pune Expressway / मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे
- D) Purvanchal Expressway / पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
- E) Agra–Lucknow Expressway / आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Government of Maharashtra inaugurated the 13.3-km 'Missing Link' project.
- महाराष्ट्र सरकार ने 13.3 किमी लंबा 'मिसिंग लिंक' प्रोजेक्ट शुरू किया।
- The project is part of the Mumbai–Pune Expressway.
- यह परियोजना मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे से संबंधित है।
- It aims to bypass the accident-prone Khandala Ghat and improve road safety.
- इसका उद्देश्य खंडाला घाट को बायपास कर सड़क सुरक्षा बढ़ाना है।
- The project will reduce travel time between Mumbai and Pune by 20–30 minutes.
- यह परियोजना मुंबई और पुणे के बीच यात्रा समय 20–30 मिनट कम करेगी।
- It is a major infrastructure upgrade to reduce accidents and ease congestion.
- यह दुर्घटनाओं को कम करने और ट्रैफिक जाम को घटाने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है।
- The initiative strengthens connectivity and transport efficiency.
- यह कनेक्टिविटी और परिवहन दक्षता को मजबूत करता है।





Ques: With the addition of 12 new sites in 2026, what is the total number of UNESCO Global Geoparks worldwide?

प्रश्न: 2026 में 12 नए स्थलों के जुड़ने के बाद UNESCO ग्लोबल जियोपार्क्स की कुल संख्या कितनी हो गई है?

- A) 200
- B) 215
- C) 230
- D) 241
- E) 260

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- UNESCO designated 12 new Global Geoparks in 2026.
- यूनेस्को ने 2026 में 12 नए ग्लोबल जियोपार्क्स को मान्यता दी।
- With this addition, the total number of geoparks has reached 241 sites across 51 countries.
- इस जोड़ के साथ कुल जियोपार्क्स की संख्या 51 देशों में 241 हो गई है।
- These geoparks cover an area of over 882,000 square kilometres.
- ये जियोपार्क्स 882,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं।
- The newly added geoparks are located in countries like China, France, Greece, Ireland, Japan, Malaysia, Portugal, Russia, Tunisia (first time), and Uruguay.
- नए जियोपार्क्स चीन, फ्रांस, ग्रीस, आयरलैंड, जापान, मलेशिया, पुर्तगाल, रूस, ट्यूनीशिया (पहली बार) और उरुग्वे में स्थित हैं।
- UNESCO Global Geoparks were established in 2015 to protect geological heritage and promote sustainable development and education.
- UNESCO ग्लोबल जियोपार्क्स की स्थापना 2015 में भूवैज्ञानिक विरासत की रक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- Each geopark is designated for a period of four years, after which it is revalidated.
- प्रत्येक जियोपार्क को 4 वर्षों के लिए मान्यता दी जाती है, जिसके बाद पुनः सत्यापन किया जाता है।





Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Total Geoparks (2026) – 241
- कुल जियोपार्क्स (2026) – 241
- Total Countries – 51
- कुल देश – 51
- Established – 2015
- स्थापना – 2015
- Duration – 4 Years (Revalidation required)
- अवधि – 4 वर्ष (पुनः मान्यता आवश्यक)

New Geoparks (2026):

- Changshan (China)
- Mt. Siguniang (China)
- Terres d'Hérault (France)
- Nisyros (Greece)
- Joyce Country and Western Lakes (Ireland)
- Mine-Akiyoshidai Karst Plateau (Japan)
- Lenggong (Malaysia)
- Sarawak Delta (Malaysia)
- Algarvensis (Portugal)
- Toratau (Russia)
- Dahar (Tunisia)
- Manantiales Serranos (Uruguay)





Ques: Rajasthan Royals is being acquired by which group for \$1.65 billion?

प्रश्न: राजस्थान रॉयल्स को \$1.65 बिलियन में किस समूह द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है?

- A) Tata Group / टाटा समूह
- B) Mittal Family & Adar Poonawalla / मित्तल परिवार और अदार पूनावाला
- C) Reliance Group / रिलायंस समूह
- D) Adani Group / अडानी समूह
- E) Vedanta Group / वेदांता समूह

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Mittal family, in partnership with Adar Poonawalla, is set to acquire Rajasthan Royals.
- मित्तल परिवार, अदार पूनावाला के साथ मिलकर राजस्थान रॉयल्स का अधिग्रहण करेगा।
- The deal is valued at approximately \$1.65 billion, making it one of the largest in Indian Premier League history.
- यह सौदा लगभग \$1.65 बिलियन का है और इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास के सबसे बड़े सौदों में से एक है।
- The Mittal family will hold around 75% stake, while Adar Poonawalla will hold about 18%.
- मित्तल परिवार के पास लगभग 75% और अदार पूनावाला के पास लगभग 18% हिस्सेदारी होगी।
- The remaining 7% stake will be held by existing investors including Manoj Badale.
- शेष 7% हिस्सेदारी मनोज बदाले जैसे निवेशकों के पास रहेगी।
- The deal includes associated teams such as Paarl Royals (South Africa) and Barbados Royals (Caribbean).
- इस डील में पार्ल रॉयल्स और बारबाडोस रॉयल्स जैसी टीमों भी शामिल हैं।
- The transaction is expected to close in Q3 2026, subject to approvals from Board of Control for Cricket in India, Competition Commission of India, and IPL Governing Council.
- यह सौदा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आदि की मंजूरी के बाद पूरा होगा।
- The new board will include Lakshmi N Mittal, Aditya Mittal, Vanisha Mittal Bhatia, Poonawalla, and Badale.
- नई बोर्ड में लक्ष्मी एन मित्तल, आदित्य मित्तल, वनीशा मित्तल-भाटिया आदि शामिल होंगे।





Ques: Rajasthan Royals is being acquired by which group for \$1.65 billion?

प्रश्न: राजस्थान रॉयल्स को \$1.65 बिलियन में किस समूह द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है?

- A) Tata Group / टाटा समूह
- B) Mittal Family & Adar Poonawalla / मित्तल परिवार और अदार पूनावाला
- C) Reliance Group / रिलायंस समूह
- D) Adani Group / अडानी समूह
- E) Vedanta Group / वेदांता समूह

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Mittal family, in partnership with Adar Poonawalla, is set to acquire Rajasthan Royals.
- मित्तल परिवार, अदार पूनावाला के साथ मिलकर राजस्थान रॉयल्स का अधिग्रहण करेगा।
- The deal is valued at approximately \$1.65 billion, making it one of the largest in Indian Premier League history.
- यह सौदा लगभग \$1.65 बिलियन का है और इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास के सबसे बड़े सौदों में से एक है।
- The Mittal family will hold around 75% stake, while Adar Poonawalla will hold about 18%.
- मित्तल परिवार के पास लगभग 75% और अदार पूनावाला के पास लगभग 18% हिस्सेदारी होगी।
- The remaining 7% stake will be held by existing investors including Manoj Badale.
- शेष 7% हिस्सेदारी मनोज बदाले जैसे निवेशकों के पास रहेगी।
- The deal includes associated teams such as Paarl Royals (South Africa) and Barbados Royals (Caribbean).
- इस डील में पार्ल रॉयल्स और बारबाडोस रॉयल्स जैसी टीमों भी शामिल हैं।
- The transaction is expected to close in Q3 2026, subject to approvals from Board of Control for Cricket in India, Competition Commission of India, and IPL Governing Council.
- यह सौदा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आदि की मंजूरी के बाद पूरा होगा।
- The new board will include Lakshmi N Mittal, Aditya Mittal, Vanisha Mittal Bhatia, Poonawalla, and Badale.
- नई बोर्ड में लक्ष्मी एन मित्तल, आदित्य मित्तल, वनीशा मित्तल-भाटिया आदि शामिल होंगे।





- The deal strengthens IPL's global investment appeal and franchise valuation growth.
- यह सौदा IPL के वैश्विक निवेश आकर्षण को मजबूत करता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Rajasthan Royals Founded – 2008
- स्थापना – 2008
- Home Ground – Sawai Mansingh Stadium
- घरेलू मैदान – सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर
- Indian Premier League Founded – 2008
- IPL स्थापना – 2008
- BCCI President – Mithun Manhas
- BCCI अध्यक्ष – मिथुन मनहास
- IPL Chairman (2026) – Arun Singh Dhumal
- IPL चेयरमैन – अरुण सिंह धूमल

EXAM
Genius





Ques: Indian scientist Parveen Shaikh was awarded the 2026 Whitley Award for conserving which endangered species?

प्रश्न: भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख को 2026 व्हिटली अवॉर्ड किस लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए दिया गया?

- A) Great Indian Bustard / ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
- B) Snow Leopard / हिम तेंदुआ
- C) Red Panda / रेड पांडा
- D) Gangetic Dolphin / गंगा डॉल्फिन
- E) Indian Skimmer / इंडियन स्किमर

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Parveen Shaikh received the 2026 Whitley Award for her efforts in protecting the endangered Indian Skimmer.
- परवीन शेख को 2026 व्हिटली अवॉर्ड इंडियन स्किमर के संरक्षण के लिए दिया गया।
- The award is given by the UK-based Whitley Fund for Nature.
- यह पुरस्कार यूके स्थित व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा दिया जाता है।
- She is associated with the Bombay Natural History Society.
- वह बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से जुड़ी हैं।
- She launched the “Guardians of the Skimmer” initiative, involving local communities to protect nesting sites.
- उन्होंने “गार्डियंस ऑफ द स्किमर” पहल शुरू की, जिसमें स्थानीय समुदायों को शामिल किया गया।
- Another Indian awardee is Barkha Subba, who is working to protect the Himalayan salamander in Darjeeling Himalaya.
- एक अन्य भारतीय विजेता बरखा सुब्बा हैं, जो दार्जिलिंग हिमालय में हिमालयन सैलामेंडर के संरक्षण पर काम कर रही हैं।
- The award provides £50,000 funding for one year to support biodiversity conservation projects.
- इस पुरस्कार के तहत एक वर्ष के लिए £50,000 की फंडिंग दी जाती है।





Recent News Headlines Related to Awards & Winners :

- 4th edition of the GEM Award : Guntur Municipal Corporation (GMC), Andhra Pradesh
- जीईएम पुरस्कार का चौथा संस्करण: गुंटूर नगर निगम (जीएमसी), आंध्र प्रदेश
- 9th Prof. M.S. Swaminathan Award : Dr. Ch. Srinivasa Rao
- 9वां प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन पुरस्कार : डॉ. च. श्रीनिवास राव
- Harvard South Asian 'Person of the Year' 2026 : Indian actress Sayani Gupta
- हार्वर्ड साउथ एशियन 'पर्सन ऑफ द ईयर' 2026: भारतीय अभिनेत्री सयानी गुप्ता
- WWF National Award : Botany researcher N. Alim Yusuf
- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ राष्ट्रीय पुरस्कार: वनस्पति विज्ञान शोधकर्ता एन. अलीम यूसुफ
- Femina Miss India World 2026 : Sadhvi Sail from Goa
- फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026: गोवा की साध्वी सेल
- WWF 'Machchli National Award' : Anita Chaudhary, a forest guard at Shergarh Wildlife Sanctuary
- WWF 'मच्छली नेशनल अवॉर्ड' : शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में कार्यरत अनीता चौधरी
- Mrs International World Classic 2026 : Geetanjali Om Parkash
- मिसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026: गीतांजलि ओम प्रकाश
- President's Police Colour, the highest honour for a police force in India : Odisha Police
- राष्ट्रपति पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है, जो भारत में किसी पुलिस बल के लिए सर्वोच्च सम्मान : ओडिशा पुलिस
- Lifetime Achievement Award at the International Film Festival of Delhi 2026 : Veteran Telugu actor Nandamuri Balakrishna
- इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली 2026 में लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड : अनुभवी तेलुगु अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण





Ques: Which state has launched India's first digital grievance redressal system for gig workers?

प्रश्न: गिग वर्कर्स के लिए भारत का पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया है?

- A) Maharashtra / महाराष्ट्र
- B) Tamil Nadu / तमिलनाडु
- C) Karnataka / कर्नाटक
- D) Telangana / तेलंगाना
- E) Kerala / केरल

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Karnataka has launched India's first digital grievance redressal system for gig workers.
- कर्नाटक ने गिग वर्कर्स के लिए भारत का पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम शुरू किया।
- The portal is called Integrated Public Grievance Redressal System (IPGRS).
- इस पोर्टल का नाम इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है।
- It acts as a bridge between gig workers and platform aggregators.
- यह गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स के बीच सेतु का काम करता है।
- Workers can file complaints related to pay, working conditions, and disputes.
- वर्कर्स वेतन, कार्य स्थितियों और विवादों से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- The initiative is developed by the Karnataka Platform-based Gig Workers Board.
- यह पहल कर्नाटक प्लेटफॉर्म-बेस्ड गिग वर्कर्स बोर्ड द्वारा विकसित की गई है।
- Every platform must form an Internal Dispute Resolution Committee (IDRC).
- प्रत्येक प्लेटफॉर्म को आंतरिक विवाद समाधान समिति (IDRC) बनानी होगी।
- The system ensures time-bound grievance resolution and transparency.
- यह प्रणाली समयबद्ध समाधान और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।
- It formalizes the gig economy by providing a legal dispute resolution framework.
- यह गिग इकोनॉमी को कानूनी ढांचे के साथ औपचारिक बनाता है।





Ques: Where was the world's largest underwater national flag unfurled, setting a Guinness World Record?

प्रश्न: दुनिया का सबसे बड़ा पानी के नीचे राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) कहाँ फहराया गया, जिसने गिनीज रिकॉर्ड बनाया?

- A) Marina Beach / मरीना बीच
- B) Juhu Beach / जुहू बीच
- C) Radhanagar Beach / राधानगर बीच
- D) Kovalam Beach / कोवलम बीच
- E) Puri Beach / पुरी बीच

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Andaman and Nicobar Administration set a Guinness World Record by unfurling the largest underwater national flag.
- अंडमान और निकोबार प्रशासन ने सबसे बड़ा पानी के नीचे राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया।
- The event took place at Radhanagar Beach on Swaraj Dweep (Havelock Island).
- यह आयोजन राधानगर बीच पर हुआ।
- The tricolour measured approximately 60m × 40m.
- तिरंगे का आकार लगभग 60 मीटर × 40 मीटर था।
- Over 200 divers, including personnel from the Indian Navy, Police, Forest Department, and Indian Coast Guard, participated.
- इस अभियान में भारतीय नौसेना, पुलिस, वन विभाग और भारतीय तटरक्षक सहित 200 से अधिक गोताखोर शामिल हुए।
- The initiative aimed to promote the Andaman and Nicobar Islands as a global diving destination.
- इस पहल का उद्देश्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को वैश्विक डाइविंग गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना था।
- Three school students were among the youngest participants.
- तीन स्कूली छात्र इस आयोजन के सबसे कम उम्र के प्रतिभागियों में शामिल थे।





Ques: Pan-India Fire Safety Week 2026 is observed between which dates?

प्रश्न: पैन-इंडिया फायर सेफ्टी वीक 2026 किस अवधि में मनाया जाता है?

- A) 1–7 May / 1–7 मई
- B) 3–9 May / 3–9 मई
- C) 4–10 May / 4–10 मई
- D) 5–11 May / 5–11 मई
- E) 10–16 May / 10–16 मई

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Ministry of Health and Family Welfare will observe a pan-India 'Fire Safety Week' from May 4 to May 10, 2026.
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 4 से 10 मई 2026 तक 'फायर सेफ्टी वीक' मनाएगा।
- The initiative aims to raise awareness about fire prevention and mitigation in healthcare facilities.
- इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में आग से बचाव और जोखिम कम करने के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
- The programme will be conducted in collaboration with all States/UTs and relevant ministries/departments.
- यह कार्यक्रम सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से आयोजित होगा।
- The week will be inaugurated at Kartavya Bhawan under the leadership of Union Health Secretary Punya Salila Srivastava.
- इसका उद्घाटन कर्तव्य भवन में पुण्य सलिला श्रीवास्तव के नेतृत्व में होगा।
- A pledge on 'Fire Safety in Health Facilities' will be administered during the inaugural event.
- उद्घाटन के दौरान अग्नि सुरक्षा पर शपथ दिलाई जाएगी।
- Activities include awareness campaigns, mock drills, capacity-building, and dissemination of protocols.
- गतिविधियों में जागरूकता अभियान, मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण शामिल हैं।
- The initiative aims to strengthen preparedness, emergency response, and evacuation procedures.
- इसका उद्देश्य आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करना है।





- It reflects the government's commitment to protecting patients, healthcare workers, and infrastructure.
- यह सरकार की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Ministry – Ministry of Health and Family Welfare
- मंत्रालय – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- Union Health Secretary – Punya Salila Srivastava
- केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव – पुण्य सलिला श्रीवास्तव
- Objective – Fire Safety Awareness in Healthcare Facilities
- उद्देश्य – स्वास्थ्य संस्थानों में अग्नि सुरक्षा जागरूकता
- Duration – 4–10 May 2026
- अवधि – 4–10 मई 2026

EXAM
Genius





Ques: World Tuna Day is observed every year on which date?

प्रश्न: विश्व टूना दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है?

- A) 1 May / 1 मई
- B) 2 May / 2 मई
- C) 3 May / 3 मई
- D) 5 May / 5 मई
- E) 8 May / 8 मई

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- World Tuna Day is observed every year on 2 May to promote sustainable fishing and conservation of tuna.
- विश्व टूना दिवस हर वर्ष 2 मई को टूना मछली के सतत मत्स्य पालन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।
- Tuna is a highly nutritious Tuna, rich in Omega-3 fatty acids, proteins, minerals, and Vitamin B12.
- टूना एक अत्यधिक पौष्टिक मछली है, जिसमें ओमेगा-3, प्रोटीन, खनिज और विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
- It plays an important role in global food security and marine ecosystems.
- यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

EXAM
Genius





Important days :

- 6 April : International Day of Sport for Development and Peace (theme for 2026 is “Sport: Building Bridges, Breaking Barriers.”)
- 7 April : World Health Day (Theme for 2026: “Together for health. Stand with science.”)
- 7 April : International Day of Reflection on the 1994 Genocide against the Tutsi in Rwanda
- 9 April : 61st Central Reserve Police Force (CRPF) Valour Day, also known as Shaurya Diwas
- 10 April : World Homoeopathy Day (Theme for 2026: “Homoeopathy for Sustainable Health”.)
- 11 April : World Parkinson’s Day (Theme for the year: “Bridge the Care Gap.”)
- 12 April : International Day of Human Space Flight (First Observance 2011)
- 12 April : International Day for Street Children 2026 (Theme 2026 Protect, not Punish)
- 12 April : Siachen Day (commemorates the success of Operation Meghdoot conducted in 1984)
- 14 April : World Chagas Disease Day
- 14 April : Ambedkar Jayanti
- 14 April : World Quantum Day (First Observance 2022) (Theme 2026 Shaping the Quantum Workforce)
- 15 April : International Wellness Day
- 15 April : World Art Day (2026 theme is “A Garden of Expression: Cultivating Community through Art.”)
- 16 April : World Voice Day 2026 (Theme 2026 Caring for Our Voices)
- 17 April : World Hemophilia Day (Theme: “Diagnosis: First step to care”)
- 18 April : World Heritage Day (2026 theme is “Emergency Response for Living Heritage in Contexts of Conflicts and Disasters”.)
- 19 April : World Liver Day 2026 (Theme 2026 Solid Habits, Strong Liver)
- 20 April : Chinese Language Day
- 21 April : World Creativity and Innovation Day (Theme 2026: “Harnessing Creativity for Global Progress”)





IMPORTANT ONE - LINER Current Affairs

India's agriculture exports recorded a growth of 2.8%, reaching \$52.55 billion in 2025–26, up from \$51.12 billion in 2024–25, despite global economic uncertainties.

China National Space Administration launched Pakistan's PRSC-EO3 satellite using a Long March-6 rocket from Taiyuan Satellite Launch Center, Shanxi, marking the 640th mission of the Long March series.

Ministry of Statistics and Programme Implementation has proposed the creation of a new Index of Service Production (ISP). The index aims to measure the performance of India's services sector on a monthly basis. It will adopt 2024–25 as the base year.

Bharat Heavy Electricals Limited signed a Licensing Agreement for Transfer of Technology (LATOT) with Naval Science and Technological Laboratory, a lab under Defence Research and Development Organisation, for the Gas Turbine-Infrared Suppression System used in naval vessels.

Nitin Gadkari announced the launch of India's first Multi-Lane Free Flow (MLFF) barrier-less tolling system. The system has been launched at Chorayasi Toll Plaza. The system uses technologies like Automatic Number Plate Recognition (ANPR) and FASTag.

The Department of Posts under the Ministry of Communications has signed a MoU with DTDC Express Limited. The agreement aims to strengthen India's logistics and e-commerce delivery network.





महत्वपूर्ण संक्षिप्त समाचार (करंट अफेयर्स)

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत के कृषि निर्यात में 2.8% की वृद्धि दर्ज की गई और यह 2024-25 के 51.12 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 52.55 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने शानक्सी के ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च-6 रॉकेट का उपयोग करके पाकिस्तान के PRSC-EO3 उपग्रह का प्रक्षेपण किया, जो लॉन्ग मार्च श्रृंखला का 640वां मिशन था।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP) बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस सूचकांक का उद्देश्य भारत के सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन को मासिक आधार पर मापना है। इसके लिए 2024-25 को आधार वर्ष माना जाएगा।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने नौसेना के जहाजों में उपयोग होने वाली गैस टरबाइन-इन्फ्रारेड दमन प्रणाली के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के तहत एक प्रयोगशाला, नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण लाइसेंसिंग समझौता (LATOT) पर हस्ताक्षर किए।

नितिन गडकरी ने भारत की पहली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) बैरियर-लेस टोलिंग प्रणाली के शुभारंभ की घोषणा की। यह प्रणाली चोरायासी टोल प्लाजा पर शुरू की गई है। यह प्रणाली स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) और फास्टैग जैसी तकनीकों का उपयोग करती है।

संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग ने डीटीडीसी एक्सप्रेस लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स डिलीवरी नेटवर्क को मजबूत करना है।

